ईरान मुद्दे पर प्रधानमंत्री का स्वतः वक्तव्य

दिनांक 17 फरवरी, 2006, संसद भवन
नई दिल्ली

5 फरवरी, 2006 को वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के शासी बोर्ड की बैठक में ईरान परमाणु मुद्दे पर भारत के मत के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए, मैं सम्मानित सदन को इस मामले के तथ्यों के बारे में जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले, मैं दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्ताव पर भारत के मत से ईरान के साथ हमारे परम्परागत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों में किसी भी तरह कमी नहीं आएगी। वस्तुतः भारत और ईरान के बीच संबंध, जैसा कि हमने बार-बार जोर दिया है, सदियों पुराने हैं। हम ईरान के साथ परस्पर हित के लिए अपने बहु-आयामी संबंधों को और मजबूत बनाकर उनका विस्तार करना चाहते हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ईरान के साथ भारत के संबंधों का महत्व केवल किसी एक मुद्दे या पहलू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संबंध द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के व्यापक विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सहयोग करते रहे हैं। हम इस संबंध को काफी महत्व देते हैं तथा अपने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे ले जाने के लिए बहुत-कुछ करना चाहते हैं। मैं इस संदर्भ में यह बात दोहराना चाहूंगा कि हम प्रस्तावित ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस परियोजना के आर्थिक पहलू की इस समय अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त परामर्शदाताओं द्वारा व्यावसायिक जांच की जा रही है। पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक जरूरी कदम है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विशिष्ट मुद्दे पर मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा जो मैंने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कही है। परमाणु अप्रसार संधि के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में ईरान के पास अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और दायित्वों के अनुरूप परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का कानूनी अधिकार है। यह ईरान के लिए लाज़िमी है कि वह इन अधिकारों का उन सुरक्षा उपायों के संदर्भ में प्रयोग करे जिन्हें उसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए स्वेच्छा से स्वीकार किया है।

इन अधिकारों और दायित्वों को 2003 के बाद के घटनाक्रम के सन्दर्भ में भी देखना होगा जब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के परमाणु कार्यकलापों से उत्पन्न अनेक प्रश्नों का जवाब मांगना शुरू किया था, जिनमें से कुछ को पिछले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बताया नहीं गया। बाद में, इन मांगों के संदर्भ में ईरान ने इनमें से कुछ कार्यकलापों की जांच में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सहयोग दिया था।

नवम्बर, 2004 में ईरान यूरोपीय संघ-3 (फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन) के साथ इस बात पर सहमत हुआ था कि जब तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा उसके पिछले परमाणु कार्यकलापों से संबंधित प्रश्नों का समाधान नहीं कर लिया जाता तब तक वह परमाणु संवर्धन और पुनःप्रसंस्करण के अपने सभी कार्यकलापों को स्वेच्छा से स्थगित कर देगा। किन्तु, पिछले वर्ष अगस्त से ईरान ने यूरेनियम हेक्साफ्लूराइड का नए सिरे से उत्पादन किया है और उसके बाद, यूरेनियम संवर्धन का काम फिर से शुरू कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महा निदेशक की उत्तरोत्तर रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि ईरान के सहयोग से अनेक प्रश्नों पर स्पष्टीकरण मिल गया है फिर भी, महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े कई प्रश्नों का अभी समाधान नहीं हो पाया है। इनमें तीसरे देशों से आयातित सेन्ट्रीफ्यूजेज का इस्तेमाल और मैटेलिक हैमिस्फियर्स के निर्माण से संबंधित डिजाइन शामिल हैं। माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि संवदेनशील प्रौद्योगिकियों के इस प्रकार के गुप्त प्रसार का स्रोत हमारे अपने पड़ोस में ही है जिसका ब्यौरा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की उत्तरोत्तर रिपोर्टों से सामने आया है। सम्मानित सदन इस बात से सहमत होगा कि भारत ऐसे प्रसार कार्यकलापों के सुरक्षा पहलुओं की अनदेखी नहीं कर सकता।

ईरान के अधिकारों और दायित्वों को बनाए रखने के उद्देश्यों और हमारे विस्तारित पड़ोस में परमाणु प्रसार कार्यकलापों से उत्पन्न हमारी सुरक्षा चिन्ताओं को ध्यान में रखकर हमने अपना रुख बनाया है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण निरन्तर इस पक्ष में रहा है कि एक ऐसा समाधान ढूंढ़ने के सभी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए जो स्वीकार्य आपसी समझौते पर आधारित हो और जिसमें ईरान के हितों तथा अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की चिन्ताओं पर ध्यान दिया जाए। हमने इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में आम-सहमति को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया है। सितम्बर, 2005 में तथा इस महीने के शुरू में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकों में हमारे रुख के पीछे यही तर्क रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि केवल इन दो अवसरों पर ही प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं बनी और वोट जरूरी हो गया है। इसके बावजूद, अभी इस महीने हुए मतदान में प्रस्ताव को न केवल रूस और चीन सहित सभी पी-5 देशों का समर्थन हासिल हुआ बल्कि अर्जेन्टीना, ब्राजील, मिश्र, घाना, सिंगापुर, यमन और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण गुट-निरपेक्ष और विकसित देशों का भी समर्थन प्राप्त हुआ।

पिछले वर्ष सितम्बर में और इस माह के शुरू में पारित प्रस्तावों में इस जरूरत पर बल दिया गया कि कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने के लिए समय दिया जाए। 5 फरवरी के हाल के प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक से कहा गया कि वे ईरान के साथ बातचीत की स्थिति तथा इन प्रश्नों के समाधान के लिए ईरान द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अवगत करायें। इसमें कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया गया है जिसमें रूस द्वारा दिए गए विकल्प पर विचार करना भी शामिल है जिसका हमने समर्थन किया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि रूस ने ईरान की संवर्धित यूरेनियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने देश में एक संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया था बशर्ते कि ईरान अपना संवर्धन कार्यक्रम स्थगित कर दे ताकि पिछले दो दशकों के अनसुलझे प्रश्नों के बारे में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बढ़ सके। रूस और ईरान इस समय इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं

कि एक सकारात्मक नतीजा सामने आएगा। हमें उम्मीद और यक़ीन है कि उत्पन्न हुए मुद्दे का अभी भी चर्चा और बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है।

मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है जिसके तहत हमने अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी में रुख अपनाया है। मैं हमारे उस अडिग विश्वास को दोहराना चाहूंगा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे, जो एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राष्ट्र और स्वाभिमानी जनता के अधिकारों और अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों से संबंधित है, का शान्तिपूर्वक, तार्किक कूटनीति और सभी पक्षों की सहमति से समाधान निकाला जा सकता है ताकि टकराव की स्थिति से बचा जा सके और स्वीकार्य समझौते के आधार पर समस्या का हल ढूंढ़ा जा सके। इसलिए हम इस मुद्दे पर बढ़ते जा रहे विवाद तथा तनाव और टकराव की संभावना से काफी चिन्तित हैं। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि इस क्षेत्र में — जहां हमारे महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हित जुड़े हुए हैं — तनाव के कारण हम सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इस क्षेत्र में 3.5 मिलियन भारतीय नागरिक हैं जिनका कल्याण हमारी सरकार के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय है।

इसलिए हम सभी संबंधितों से संयम बरतने, लचीलापन दिखाने और वार्ताएं जारी रखने का आग्रह करते हैं ताकि इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके। जैसाकि मैंने कहा है, अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी बोर्ड की अगली मीटिंग इस वर्ष मार्च महीने में होगी जिसमें अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के महा निदेशक द्वारा एक पूर्ण और नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हम आने वाले दिनों में इसमें शामिल सभी प्रमुख देशों के साथ दोस्ताना सम्बंध बनाते हुए इस बारे में कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करेंगे।

हमारी सरकार इस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातों में संतुलन बनाने की जरूरत के प्रति सचेत है। ईरान के साथ हमारे मजबूत और महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं, जिन्हें हम उस प्रकार आगे बढ़ाना चाहेंगे जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हों। ईरान के लोगों के प्रति हमारे मन में काफी आदर और सम्मान है, जिनके साथ हमारे अनेक सदियों से दोस्ताना संबंध चले आ रहे हैं। हम यह पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे कि इन संबंधों पर कोई आंच न आए।

समग्र संदर्भ जिस पर मैंने विस्तार से प्रकाश डाला है, के बारे में मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदन इस बात से सहमत होगा कि इस सरकार द्वारा अपनाया गया रुख संगत है और हमारे राष्ट्रीय हितों के सुविचारित और स्वतंत्र निर्णय के अनुरूप है। मुझे यकीन है कि इस नीति को इस सदन और हमारे राष्ट्र का समर्थन हासिल होगा।

*****